female elephant and a male calf elephant were found electrocuted in Parambikulam Sanctuary, Kerala. The electrocution was due to the low lying high tension overhead powerline on the right side of Anappaddy-Thunkkadavu Road inside the sanctuary. The power line is maintained by the Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) as part of the inter-State Parambikulam-Aliyar Project.

(c) The electricity lines passing through the sanctuary area were jointly inspected by the TNEB and the Sanctuary Staff, who identified the points where the lines are below the stipulated height of 7.1 metres. A list of such points was handed over to the TNEB and a meeting was also held between the sanctuary and TNEB officials on 20.9.1998 for rectifying all the sagging power lines and raising them to the stipulated height.

Environmental clearance for Hydro Power Plant at Nagarjuna Sagar Tail Pond Dam

639. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of EVNIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government of Andhra Pradesh has proposed construction of 2x25MW Hydro Power Generation Plant at Nagarjuna Sagar Tail Pond Dam.;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons for the delay in grant of clearance by the Ministry; and

(d) likely date by which the proposal will be cleared by the Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) and (b) Yes, Sir. The Government of Andhra Pradesh proposes to set up a 2x25MW Hydro Power Generation Plant which involves submergence of 113 hectares of forest land in tiger valley.

(c) and (d) The proposal for diversion of 113 hec. forest land has been rejected on 01.01.1997 under Forest (Conservation) Act, 1980. On a request made by the State Government, the proposal is being reviewed by a committee of wild life experts. A decision will be taken after the receipt of the report of the said committee.

वायु प्रदूषण का खतरा

640. **श्री कपिल सिब्बल**:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और पर्यावरण केंन्द्र ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि देश में वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 52,000 लोग अपना जीव्न गंवा रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन की उपर्युक्त टिप्पणी का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) एक गैर-सरकारी संगठन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा प्रकाशित एक लेख में यह अनुमान लगाया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 1995 में भारत के 36 नगरों में लगभग 52,000 कालपूर्व मौतें हुई । इन आंकड़ो की पुष्टि के लिए कोई निर्णायक आंकड़ा नहीं है ।

(ग) पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है:–

1. सरकार ने प्रदूषण के उपशमन हेतु एक विस्तृत पालिसी स्टेटमेंट तैयार किया है जिसमें विकास संबंधी योजना के पर्यावरणीय तथा आर्थिक पहलू के निवारक पहलुओं और प्रदूषण कम करने तथा स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं हेतु स्वच्छ प्रोद्योगिकियों के विकास पर जोर दिया गया है ।

2. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए तथा भीड़-भाड़ क्षेत्रों से उद्योगों के स्थानंतरण के लिए वित्तिय प्रोत्साहन दिए जा रहे है ।

3. चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई में जून, 94 से सीसे की कम मात्रा वाले पेट्रोल की शुरूआत की गई थी । इसके पश्चात उपरोक्त 4 शहरों में 1 अप्रैल, 95 से सीसा रहित पेट्रोल और कैटेलेटिक कन्वर्टरयुक्त वाहनों की शुरूआत की गई

4. सरकार सीसा रहित पेट्रोल और कैटेलेटिक कन्वर्टरयुक्त को शुरू करने के लिए तथा अधिक साफ डीजल वाहनों में कम सल्फरयुक्त डीजल के प्रयोग के

लिए चरणबद्ध तरीके से एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रही हैं। पेट्रोल और डीजल के लिए ईधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

5. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत चलित वाहनों के लिए ठोस उत्सर्जन मानक तथा नए वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं तथा विभिन्न राज्यों के यातायात विभागों द्वारा इन्हें लागू किया जा रहा है।

6. वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए विनिर्माण की अवस्था में उत्सर्जन मानक 1990 में पहली बार स्थापित किए गए थे तथा 1996 में उन्हें और अधिक कठोर बना दिया गया और अधिक कठोर बना दिया गया और अधिक कठोर उत्सर्जन मानक भी अधिसूचित किए जा चुके हैं तथा ये 1.4.2000 से प्रभावी होंगे।

7. देश के मुख्य शहरों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वाहन जनित उत्सर्जनों पर सर्वेक्षण किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों को न्यूनीकरण उपायों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

8. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग कार्यक्रम के तहत 290 मानीटरिंग स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न शहरों तथा कस्बों की परिवेशी वायु गुणवत्ता को नियमित तौर पर मानीटर किया जा रहा है।

9. उच्च प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों तथा ताप ऊर्जा प्लांटों द्वारा छोड़े गए उत्सर्जनों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो द्वारा नियमित तौर पर मानीटर किया जा रहा है तथा दोषी इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

10. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत उत्सर्जन तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए है।

Damage to wildlife sanctuaries of Assam

641. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the extent of damage caused to the natural habitat and flora and fauna of Kaziranga National Park and other wildlife sanctuaries of Assam;

(b) the steps initiated for restoration and future protection; and

(c) the name of Biosphere reserves declared for Assam and the details of its execution status, alongwith financial allocation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) Reports have been received from the State of Assam regarding the death of 651 animals in Kaziranga due to floods. The floods have also caused damage to communication network and infrastructure including patrolling camps.

(b) The restoration work has been started on war footing. For protection against poaching, home guards have been deployed and patrolling has been intensified.

(c) There are only two Biosphere Reserve in Assam i.e. Dibru-Saikhowa and Manas. During the year 1997-98 an amount Rs. 10 Lakhs and Rs. 30 Lakhs respectively have been sanctioned for these Biospheres. Activities like Eco-development, Protection, Eco-regeneration. Research and Education are undertaken under the scheme.

Forest Area Dereserved for Different Projects

642. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what area of forest has been dereserved for different projects, i.e. mining, industries, irrigation, etc. State-wise, during the last five years, till date;

(b) the details regarding the land so identified amount received, area actually covered and amount of expenditure incurred for compensatory afforestation, State-wise;

(c) whether it is a fact that huge amount on account of compensatory afforestation is still lying unutilised; and

(d) if so, whether Government have reserved that amount for the same purpose or have diverted the same for other department expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS: (SHRI BABU LAL MARANDI), (a) to (d) An area of 141812 ha. of forest land have been dereserved for different projects including mining, industries, irrigation etc. during 1993-94 to 1998-99 upto 31.10.98 under